सं.ए-45011/4/2021-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

****

नई दिल्ली, दिनांकः 10 सितम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित जुलाई, 2021 माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार के अवर्गीकृत भाग को परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अरूप श्याम

(अरूप श्याम चौधुरी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23095091

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
8. सभी सदस्य, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, सचिव(दीपम) के प्रधान निजी सचिव।
11. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव (श्री ए. गिरिधर), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री के. राजारामन, अपर सचिव (प्रशासन एंड निवेश), आर्थिक कार्य विभाग।
14. सुश्री मीरा स्वरूप, अपर सचिव और वित्त सलाहकार (वित्त)।
15. श्री ए.एम. बजाज, अपर सचिव (एफएम), आर्थिक कार्य विभाग।
16. श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव (बजट), आर्थिक कार्य विभाग।
17. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
18. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।

वरिष्ठ सलाहकार (सीएंडएसी/ एफएसएलआर/एफएस एंड सीएस)/संयुक्त सचिव (आईपीएफ)/संयुक्त सचिव (बजट)/संयुक्त सचिव (सीएंडसी)/संयुक्त सचिव(निवेश)/सलाहकार (बीसी)/सलाहकार (प्रशा.)/सलाहकार (निवेश)/सलाहकार (आर्थिक प्रभाग)/ सलाहकार (आईईआर)/सलाहकार (आईईआर)/सलाहकार (आईपीएफ)/सीएएए।

19. श्री राजेश मल्होत्रा, अपर महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

20. गार्ड फाइल – 2021

सं. ए-45011/4/2021-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

विषय: जुलाई, 2021 माह के दौरान आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार।

1. **वृहत-आर्थिक सिंहावलोकन**

भारतीय अर्थव्यवस्था लक्षित राजकोषीय राहत, मौद्रिक नीति उपायों, और त्वरित टीकाकरण अभियान के साथ कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव से उबरने के संकेत दिखा रही है। दूसरी लहर को धीमा करने के लिए विस्तार आधारित आर्थिक राहत पैकेज की राशि को 6.29 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया। आरबीआई ने बाजार की चिंताओं को कम करने और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज और विकास पर गुणक प्रभाव वाले क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को जारी रखा है।

केंद्र सरकार का लचीला कर संग्रह और विशेष रूप से सड़क और रेल क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि-पूंजीगत व्यय द्वारा संचालित निरंतर आर्थिक पुनर्बहाली के लिए अच्छा संकेत हैं। हाल ही में घोषित आर्थिक राहत पैकेज से पीएलआई योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से कैपेक्स चक्र की गति में और अधिक तेजी आने और पीपीपी परियोजनाओं और संपत्ति मुद्रीकरण हेतु प्रक्रियाओं के धारा प्रवाही होने की उम्मीद है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एएनबीआरवाई) के तहत रोजगार सहायता में और अधिक वृद्धि, सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा ऋण उपलब्धता हेतु ऋण गारंटी योजना के माध्यम से शहरी गरीबों को लक्षित समर्थन और व्यापक भारत-नेट डिजिटलीकरण कवरेज से खपत की भावना बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी ओर इस पैकेज के तहत मनरेगा कार्यान्वयन को जारी रखने के साथ निःशुल्क खाद्यान्न और बढ़ी हुई उर्वरक सब्सिडी आने वाली तिमाहियों में ग्रामीण मांग के लिए एक सुविधा के रूप में काम करेगा। टीकाकरण में तीव्र गति बनाए रखना और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की अवसंरचना के अंतर को कम करना, भारतीय अर्थव्यवस्था की सतत बहाली के लिए सबसे स्थायी प्रोत्साहन के रूप में उभरेगा।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2019-20 में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.3 प्रतिशत तक विस्तारित होने का अनुमान है (अनुबंध की तालिका 1)।

23 जुलाई, 2021 को जारी नवीनतम वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, श्रम बल भागीदारी दर अर्थात् श्रम की आपूर्ति 2018-19 में 37.5 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 40.1